



सांध्य दैनिक 4PM



कोई भी मूर्ख आलोचना, निंदा, और शिकायत कर सकता है और ज्यादातर मूर्ख करते हैं।
-डेल कार्नेगी

मूल्य ₹ 3/-

जिद...सच की

www.4pm.co.in | www.facebook.com/4pmnewsnetwork | @Editor_SanjayS | YouTube | 4pm NEWS NETWORK

वर्ष: 12 • अंक: 47 पृष्ठ: 8 • लखनऊ, सोमवार 23 मार्च, 2026

आईपीएल 2026: मुंबई की नजर छटे खिताब... 7 देखन में छोटे लगे घाव करे... 3 पीडीए के ए का मतलब आधी... 2

न डरे थे, न डरे हैं, डटें रहेंगे हम

4PM नेटवर्क पर सरकारी पाबंदियों का पहरा

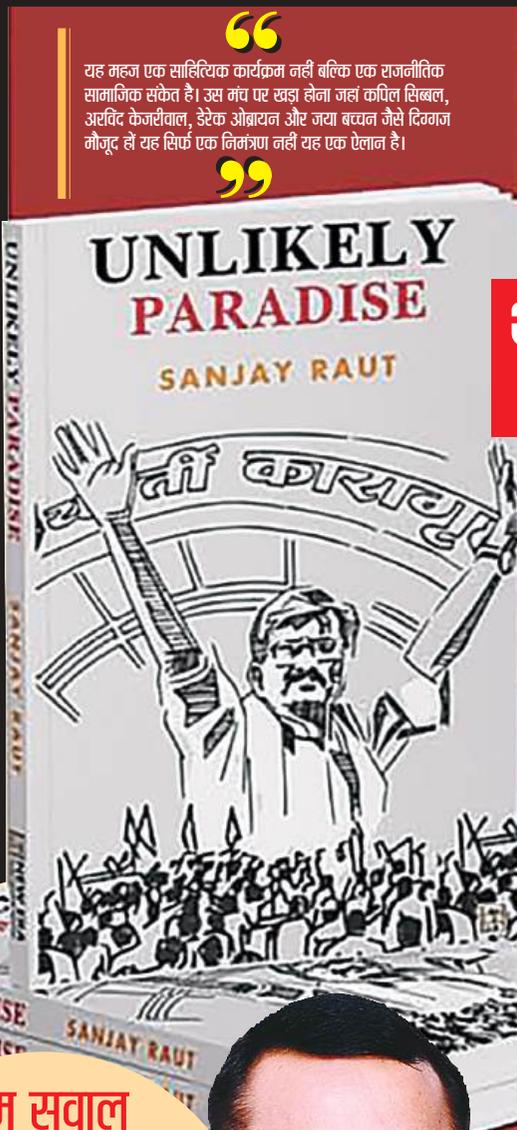
» चैनल, रील के बाद फेसबुक पेज को भी सरकार ने बनाया निशाना
□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। सरकार 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क पर पाबंदियों का पहरा लगाकर डराना चाहती है। 4पीएम के यूट्यूब चैनल पर बैन लगाया। फिर चैनल की रील पर बैन लगाया गया और ताजा कार्रवाई 4पीएम के फेसबुक पेज को भी भारत में बैन कर दिया गया।

सरकार बैन के सहारे चाहती है कि सवाल पूछने वाले थम जाएं आवाजें धीमी पड़ जाएं और सच की जगह सिर्फ एक तयशुदा कथा चलती रहे। मीडिया पर कसती लगाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ती निगरानी, और अब 4पीएम नेटवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पर पाबंदी यह सब किसी इत्तेफाक का हिस्सा नहीं है। यह एक पैटर्न है एक रणनीति है जहां असहमति को अपराध और सवाल को बगावत बना दिया गया है।

विद्रोही नजरिया बगावती तेवर

इस घरे घटनाक्रम के केंद्र में एक नाम बार-बार उभरता है और वह है सांपदाक संजय शर्मा का नाम। एक ऐसा पत्रकार जिसने सत्ता के सामने घुटने टेकने के बजाय सवाल को अपना हथियार बनाया। 4पीएम नेटवर्क के जरिए उन्होंने वो सवाल उठाए जिन्हें मुख्यधारा का मीडिया पूछने से कतराता रहा। संजय शर्मा की पत्रकारिता किसी एजेंडे का हिस्सा नहीं रही बल्कि यह सीधे जनता के मुद्दों से जुड़ी रही चाहे वह सरकारी नीतियों की खानियां हों प्रशासनिक भ्रष्टाचार हो या फिर लोकतांत्रिक संस्थाओं की गिरती साख। यही वजह है कि उनका प्लेटफॉर्म तेजी से लोकप्रिय हुआ और लोगों का भरोसा जीतने लगा। लेकिन शायद यही लोकप्रियता सत्ता को खटकने लगी। जब कोई मंच बिना डर के सच बोलने लगता है तो वह सत्ता के लिए असहज स्थिति पैदा करता है। और फिर शुरू होता है दबाव नोटिस और अंत में-बैन। सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक फेसबुक पेज या चैनल को बंद कर देने से आवाजें खत्म हो जाएंगी? क्या संजय शर्मा जैसे पत्रकार चुप बैठ जाएंगे? इतिहास बताता है कि ऐसे हर प्रयास ने आवाजों को और मजबूत ही किया है।

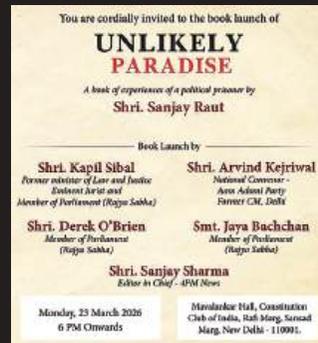


“यह महज एक साहित्यिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक राजनीतिक सामाजिक संकेत है। उस मंच पर खड़ा होना जहां कपिल सिब्बल, अरविंद केजरीवाल, डेरेक ओब्रायन और जया बच्चन जैसे दिग्गज मौजूद हैं यह सिर्फ एक निमंत्रण नहीं यह एक ऐलान है।”

4PM रुका नहीं है और अब रुकेगा भी नहीं

यह वही साहस है जो बंद दरवाजों के सामने भी बोलता है। यह वही जिद है जो हर रोक के बाद और ज्यादा मजबूत होकर खड़ी होती है। अगर मंच छिनोगे तो सड़कें मंच बन जाएंगी। अगर माइक्रोफोन बंद करोगे तो आवाजें और उंची हो जाएंगी। 4पीएम को रोकने की कोशिशें कोई नई बात नहीं हैं। लेकिन हर बार इन कोशिशों ने सिर्फ एक चीज साबित की है कि यह आवाज दबने के लिए नहीं बनी। यह आवाज लड़ने के लिए बनी है सवाल पूछने के लिए बनी है और सच को सामने लाने के लिए बनी है।

शीर्ष पर संजय शर्मा, एक मंच एक किताब और वह उपस्थिति जो किसी भी बैन से कहीं ज्यादा बड़ी है



सवाल तो पूछते रहेंगे हम

लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत सवाल है। अगर सवाल खत्म हो गए तो लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगा। आज जो हो रहा है वह इसी मूल भावना पर हमला है। मीडिया का काम सरकार की तारीफ करना नहीं बल्कि उसकी जवाबदेही तय करना है। लेकिन जब मीडिया पर ही पाबंदियां लगाने लगे तो यह खतरे की घंटी है। 4पीएम नेटवर्क पर कार्रवाई इसी दिशा में एक बड़ा संकेत है। लेकिन यह भी सच है कि सवाल पूछने की आदत को खत्म नहीं किया जा सकता। यह समाज के डीएनए में होता है। एक प्लेटफॉर्म बंद होगा तो दूसरा खड़ा होगा। एक आवाज दबेगी तो सौ नई आवाजें उठेंगी। सवाल पूछना सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। और हम इस जिम्मेदारी से पीछे हटने वाले नहीं हैं।

सरकार चाहती है चापलूसी की कथा

पहले चैनल पर रोक फिर रील पर शिकंजा और अब फेसबुक पेज तक को बैन कर देना। यह सिर्फ तकनीकी कार्रवाई नहीं है। यह एक संदेश है। जो पूछेगा वो बड़ेगा नहीं। लेकिन शायद सत्ता यह भूल रही है कि सवाल पूछना कोई जर्मन नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। हम डरने वालों में से नहीं हैं। हमें डराने की कोशिश गिरती तेज होगी हमारी आवाज उतनी ही बुलंद होगी। इतिहास गवाह है कि जब जब सत्ता ने डर का हथियार उठाया है तब तब समाज ने सवाल को और धारदार बनाया है। और आज भी वही हो रहा है। अगर सरकार सोचती है कि बैन करके दबाव बनाकर या आवाजों को बंद करके सच्चाई को चुपचाप लुप्त करे तो यह उसकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि सवाल बंद नहीं होते वह रास्ते बदल लेते हैं। वह चैनल से निकलकर सोशल मीडिया में आते हैं वहां से सड़कें पर उतरते हैं और फिर एक आंदोलन बन जाते हैं।

हम सवाल पूछते रहेंगे

आज 4पीएम नेटवर्क पर लगी पाबंदी सिर्फ एक संस्था की कहानी नहीं है। यह उस हर आवाज की कहानी है जो सच बोलने की हिम्मत रखती है। और हम साफ कह देना चाहते हैं कि हम डरते नहीं, हम झुकेंगे नहीं? हम सच की राह पर चलते हुए सवाल पूछते रहेंगे।



सच के साथी संजय शर्मा

देश की लीजेंड राजनीतिक पर्सनलटी संजय राउत की किताब अनलाइकली पैराडाइज के लॉन्च में शामिल होना कोई साधारण घटना नहीं है। यह महज एक साहित्यिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक राजनीतिक सामाजिक संकेत है। उस मंच पर खड़ा होना जहां कपिल सिब्बल, अरविंद केजरीवाल, डेरेक ओब्रायन और जया बच्चन जैसे दिग्गज मौजूद हैं यह सिर्फ एक निमंत्रण नहीं यह एक ऐलान है। यह ऐलान है कि आवाजों को कैद नहीं किया जा सकता। यह जवाब है उन तमाम ताकतों के लिए जो यह मान बैठी हैं कि डर

दिखाकर दबाव बनाकर और प्लेटफॉर्म छिनकर सच को खत्म किया जा सकता है। उन्हें समझ लेना चाहिए सच किसी सर्वर पर नहीं चलता सच किसी एक चैनल की मोहताज नहीं होता। सच वहां होता है जहां उसे कहने का साहस होता है। आज जब कुछ लोग यह सोच रहे हैं कि 4पीएम रुक गया है उन्हें यह समझ लेना चाहिए यह सिर्फ एक पड़ाव है अंत नहीं। यह एक नई शुरुआत है एक नए तेवर के साथ। 4पीएम रुका नहीं है और अब रुकेगा भी नहीं। सच यह है कि आवाजें बंद नहीं होतीं वह रूप बदलती हैं। जितना दबाओगे उतना उभरेंगी। जितना रोकने की कोशिश करोगे उतनी तेजी से फैलेंगी। आज उसी सच का एक मंच एक किताब और वह उपस्थिति जो किसी भी बैन से कहीं ज्यादा बड़ी है।

अपनी आवाज बुलंद रखेंगे

डर एक ऐसा हथियार है जिसे सत्ता बार बार इस्तेमाल करती है। लेकिन हर बार यह हथियार कामयाब नहीं होता। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डर को चुनौती देते हैं। हम न पहले डरे थे न आज डर रहे हैं और न ही आगे डरेंगे। क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ एक चैनल या एक पत्रकार की नहीं है यह लड़ाई सच और झूठ के बीच की है। अगर आज हम चुप हो गए तो कल सवाल पूछने का अधिकार ही खत्म हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम डटकर खड़े रहें अपनी आवाज बुलंद रखें और हर उस कोशिश का विरोध करें जो हमें डराने के लिए की जा रही है। और जब तक सवाल जिंदा हैं तब तक लोकतंत्र भी जिंदा रहेगा।

पीडीए के ए का मतलब आधी आबादी जिसको मिलेगी पूरी आजादी : अखिलेश

» सपा प्रमुख ने पीडीए के नारे को और मजबूती व बड़ा आकार दिया

4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को पीडीए के नारे को और मजबूती व बड़ा आकार दिया है। सपा प्रमुख ने कहा कि अब तक पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की आवाज माने जाने वाले इस शब्द में का अर्थ अब आधी आबादी (महिलाएं) भी होगा।

अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्त्री सम्मान-समृद्धि योजना लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान 'पीडीए' शब्द पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों को संबोधित करने के लिए गढ़ा था। यादव ने 'एक्स' अग्रणी महिलाओं के साथ अपनी पत्नी सांसद डिंपल यादव समेत खुद की तस्वीरें साझा करते हुए कहा, "आधी आबादी की पूरी आजादी व उनकी हिफाजत के साथ-साथ उनके हक-अधिकार, सशक्तिकरण व सबलीकरण के लिए हम सब सदैव कटिबद्ध-प्रतिबद्ध रहे हैं और रहेंगे।"

मोदी सरकार हवाई सफर महंगा कर रही है : केजरीवाल

4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घरेलू हवाई किराए पर लगी सीमा को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए चेतावनी दी कि इससे टिकटों की कीमतें मध्यम वर्ग की पहुंच से बाहर हो सकती हैं।

एक पोस्ट में केजरीवाल ने कहा कि हवाई किराया मध्यम वर्ग की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। मोदी सरकार हवाई किराए पर लगी सीमा को हटा रही है, जिससे टिकटों की कीमतों में भारी मुद्रास्फीति हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को इसके बजाय किराए को अधिक प्रभावी ढंग से विनियमित करने पर ध्यान देना चाहिए और जोर देकर कहा कि हवाई यात्रा अब विलासिता नहीं, बल्कि मध्यम वर्ग के लिए एक आवश्यकता है। यह टिप्पणी नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा घरेलू हवाई यात्रा पर लगाए गए अस्थायी किराया प्रतिबंधों को वापस लेने के बाद आई है, जिसमें मंत्रालय ने पूरे क्षेत्र में उड़ान संचालन में स्थिरता का हवाला दिया है।



सरकार बनने पर स्त्री सम्मान-समृद्धि योजना लाएंगे

उन्होंने कहा, जब परिवार-समाज और देश को मजबूत करने वालों को सम्मान मिलता है तो उनका मान और मनोबल दोनों बढ़ता है। हम पीडीए में शामिल 'ए' मतलब 'आधी आबादी'

अर्थात हर बच्ची, युवती, नारी, महिला को सामाजिक-आर्थिक रूप से समान सम्मान देने और अपने पैरों पर खड़े होने व उन्हें समृद्ध करने के लिए 'स्त्री सम्मान-समृद्धि योजना' लाएंगे।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि "समाजवादी पेंशन" को फिर से लाकर हम महिलाओं की ताकत बढ़ाएंगे और साथ ही 'उग्र की संपूर्ण उन्नति' के अपने संकल्प को निभाएंगे।

दूसरे दलों को बदनाम करने का काम कर रही फिल्में

धुरंधर-2 पर बोलते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि सरकार ऐसी फिल्में बनाने में पैसा खर्च कर रही है जो दूसरे दलों को बदनाम करने का काम करती हैं। मुझे लगता है कि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तभी तो फिल्मों की रिलीज पर भी पैसे बहाए जा रहे हैं। बता दें कि फिल्म के अंदर पूर्व विधायक अतीक अहमद का हृष्ट लीक और आतंकी कनेक्शन दिखाया गया है, इससे समाजवादी पार्टी खफा है। उसने इसपर कड़ा विरोध जताया था।

मधुरा में फरसा वाले बाबा की मौत पर साधा योगी सरकार पर निशाना

अखिलेश यादव ने मधुरा में फरसा वाले बाबा की मौत पर योगी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए, अखिलेश ने कहा कि जरा सोचिए मधुरा में क्या हुआ, एक संत की हत्या हो गई, और अब तरह-तरह की कहानियां सुनाई जा रही हैं, कौन जिम्मेदार था, मकान मालिक कौन था, प्रशासन क्या कर रहा था, अधिकारी क्या कर रहे थे इन सभी बातों पर गंभीरता से विचार लेना चाहिए।

मंत्री संजय निषाद ने भाजपा को दी चेतावनी

4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि 2027 के चुनावों के लिए उनकी पार्टी का भाजपा के साथ गठबंधन आरक्षण के मूल मुद्दे पर आधारित है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि उसने समुदाय की मांगों पर दरवाजा बंद कर दिया था।



भाजपा द्वारा समुदाय की विरासत का सम्मान करने और एक अलग मत्स्य मंत्रालय बनाने के प्रयासों को स्वीकार करते हुए, मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि वे आरक्षण के समर्थक बने हुए हैं और अब सत्ताधारी दल को इस प्राथमिक वादे को पूरा करके अपनी प्रतिबद्धता साबित करनी होगी। निषाद ने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी में था। उन्होंने मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए, इसलिए मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी। उन्होंने आरक्षण के मेरे मुद्दे पर एक भी सवाल नहीं उठाया। आरक्षण का मुद्दा मेरी पार्टी की प्राथमिकता है। ताल-

गठबंधन आरक्षण के मूल मुद्दे पर आधारित

घाट नदियों का मुद्दा, हमारी विमुक्त जनजातियों की शिक्षा, ये मुद्दे केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पहले यह धारणा थी कि भाजपा आरक्षण के खिलाफ है, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया। उन्होंने यह भी कहा कि पहले यह धारणा थी कि भाजपा आरक्षण के खिलाफ है, लेकिन उन्होंने उच्च जातियों को 10 प्रतिशत और महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया है, इसलिए यह आरोप दूर हो गया है। निषाद ने कहा कि वे आरक्षण के पैरोकार हैं और भाजपा के जवाब का इंतजार कर रहे हैं कि वे इस पर कब कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने का सवाल तभी उठेगा जब भाजपा अपने दरवाजे बंद कर देगी। भाजपा को ही जवाब देना होगा क्योंकि मैं आरक्षण का पैरोकार हूँ; मैं इसकी वकालत करता हूँ। भाजपा को जवाब देना होगा कि वह आरक्षण कब देगी। वे इस पर काम कर रहे हैं और बड़े कदम उठा रहे हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि वे इसे लागू करेंगे।

अब्दुल बासित की गीदड़ भभकी पर भड़की प्रियंका चतुर्वेदी

» बोलीं शिवसेना यूबीटी सांसद - मानसिक संतुलन खो बैठे सारे पाकिस्तानी

4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रह चुके बासित ने एक टेलीविजन डिबेट में अमेरिका के हमले के जवाब में भारत पर हमले को लेकर शंखी बघारी। पाकिस्तान में टीवी चैनल पर सवालों का जवाब देते हुए गीदड़भभकी दी।

उनके इस बयान पर शिवसेना की नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित द्वारा भारते को लेकर दिए गए बयान पर कहा, जो ये बोल रहे हैं इतना हास्यास्पद है, इनको लगता है भारत हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहेगा और सबसे पहले तो ये जो अब्दुल बासित हैं, उनको बताएं कि भारत पर इतना फोकस डाल-डाल कर अपना मानसिक संतुलन सारे पाकिस्तानी खो बैठे हैं, खासकर वो जो पाकिस्तानी सत्ता में हैं और इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं।

केसी त्यागी ने थामा रालोद का दामन



4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। जेडीयू के दिग्गज नेता और नीतीश कुमार के पूर्व सलाहकार केसी त्यागी ने जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) का दामन थाम लिया है। इस बड़े राजनीतिक फेरबदल से रालोद को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसान राजनीति में त्यागी के अनुभव का लाभ मिलने की उम्मीद है, जबकि जेडीयू ने अपना एक राष्ट्रीय चेहरा खो दिया है।

जनता दल यूनाइटेड के दिग्गज नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पूर्व सलाहकार केसी त्यागी अब राष्ट्रीय लोक दल का हिस्सा बन गए हैं। पिछले काफी समय से उनके नई पार्टी में जाने की अटकलें लगाई जा रही थीं, जिस पर अब विराम लग गया है। केंद्रीय मंत्री और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी की मौजूदगी में त्यागी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि त्यागी ने हाल ही में जेडीयू के सदस्यता अभियान के दौरान अपना इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था, हालांकि उन्होंने उस वक्त इस्तीफे की कोई ठोस वजह नहीं बताई थी। जेडीयू की स्थापना से लेकर राष्ट्रीय पहचान तक का सफर

केसी त्यागी जेडीयू के उन चुनिंदा नेताओं में से थे जो 2003 में समता पार्टी और जनता दल के विलय के समय से ही नीतीश कुमार के साथ खड़े थे। जॉर्ज फर्नांडिस के दौर में वे पार्टी के महासचिव थे और बाद में उन्होंने शरद यादव व नीतीश कुमार के साथ संगठन में मुख्य प्रवक्ता और राजनीतिक सलाहकार जैसे कई महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभाली। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर जेडीयू का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता रहा है। अब रालोद में शामिल होने के बाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और किसानों की राजनीति में उनके अनुभव का बड़ा लाभ जयंत चौधरी की पार्टी को मिलने की उम्मीद है। जेडीयू छोड़ते समय केसी त्यागी ने स्पष्ट किया था कि वे दलितों, किसानों और समाज के वंचित वर्गों के व्यापक वैचारिक मुद्दों के प्रति आज भी उतने ही प्रतिबद्ध हैं जितने पहले थे। उन्होंने कहा कि लगभग 50 साल तक उनके साथी रहे नीतीश कुमार के प्रति उनका निजी सम्मान हमेशा बना रहेगा, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी पार्टी की सदस्यता का नवीनीकरण नहीं कराया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पिछले कुछ महीनों में नीतीश कुमार और त्यागी के बीच दूरियां बढ़ गई थीं, जिसके बाद उन्होंने जयंत चौधरी की पार्टी के साथ नई राजनीतिक पारी शुरू करने का फैसला किया।



क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की सदस्यता रद्द हो राज्यसभा चुनाव में वोटिंग करने वाले कांग्रेस विधायकों पर भड़के पूर्व सीएम अशोक गहलोत

4पीएम न्यूज नेटवर्क

जयपुर। देश के कई राज्यों में पिछले दिनों राज्यसभा चुनाव करवाए गए जिनमें हरियाणा ओडिशा और बिहार में हुई क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हुई। इससे पहले भी हरियाणा में कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग हुई थी लेकिन इस बार मामला बढ़ता हुआ दिख रहा है क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कांग्रेस नेता कर रहे हैं।

इस बीच पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की सदस्यता रद्द होने चाहिए। अशोक गहलोत ने कहा कि हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में हरियाणा, ओडिशा और बिहार में कांग्रेस विधायकों द्वारा हुई क्रॉस वोटिंग बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे समय में यह समझ से परे है कि



वोट दिखाने के बावजूद विधायक क्रॉस वोटिंग की हिम्मत कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इससे मुझे राजस्थान में 2018 से 2023 के बीच हुए राज्यसभा चुनावों की याद आई जिनमें हमने पार्टी हाईकमान और पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। कांग्रेस के 102 विधायक होते हुए भी 126 विधायकों के वोट कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवारों के पक्ष में मिले, जबकि इन अतिरिक्त 24 विधायकों का वोट कांग्रेस पर्यवेक्षक नहीं देख सकते थे। बिना किसी लोभ लालच ये केवल हाईकमान के हमारे ऊपर विश्वास से जो गुडविल बनी उससे संभव हो सका।

देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर 'टाइगर' की दहाड़ से बैकफुट पर भाजपा

- » झारखंड में छोटी पार्टियों या एकल विधायकों की सक्रियता चर्चा में
- » अकेले विधायक ने पेश किए 7 कटौती प्रस्ताव
- » बड़े दलों के लिए चेतावनी

रांची। देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यही कहावत आजकल झारखंड में चरित्रार्थ हो रही है। झारखंड विधानसभा में वैसे तो भाजपा सबसे बड़ा विपक्ष है पर वह कई मामलों में पिडछता दिखाई दे रहा है। दूसरी राज्य की सत्ता में बैठी झामुमो की हेमंत सरकार जनता के बीच अपनी पैठ मजबूत करती जा रही है। हालांकि उसकी बहुत सी योजनाएं लोगों को पसंद नहीं आती हैं। पर उनके मुद्दों को वह उतनी मुखरता से नहीं उठा पा रही जितनी मुखरता से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के एकमात्र विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो ने उठाया। अपनी सक्रियता से महतो ने मुख्य विपक्षी दल भाजपा को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने सात कटौती प्रस्ताव पेश कर न केवल सरकार को घेरा, बल्कि भाजपा की निष्क्रियता को भी उजागर किया।

एकमात्र विधायक जयराम महतो ने सात कटौती प्रस्ताव पेश किए। इस बात को बाहर आने के बाद भाजपा नेतृत्व ने अपने विधायकों की कम सक्रियता पर फटकार लगाई। झारखंड विधानसभा के हालिया बजट सत्र में एक दिलचस्प राजनीतिक परिदृश्य उभरकर सामने आया, जहां संख्या बल में अकेला लेकिन सक्रियता में आगे रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) के इकलौते विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो ने मुख्य विपक्षी दल भाजपा को सदन में पीछे छोड़ दिया।



अभिभाषण पर कटौती प्रस्ताव तक नहीं ला पाई भाजपा

जयराम महतो की यह सक्रियता इसलिए भी खास मानी जा रही है, क्योंकि वे सदन में अकेले विधायक हैं, जबकि भाजपा के पास 21 विधायकों का मजबूत दल मौजूद है। इसके बावजूद भाजपा के विधायक कटौती प्रस्ताव लाने और बहस में प्रभावी भागीदारी दिखाने में पीछे रह गए। इसे भाजपा की रणनीतिक चूक के रूप में देखा जा रहा है।

पक्ष के साथ विपक्ष भी निशाने पर

जयराम महतो ने अपने भाषणों में सरकार की नीतियों के साथ-साथ भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने सदन में विपक्ष की चुप्पी को मुद्दा बनाते हुए कहा कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है, लेकिन यहां विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में विफल नजर आ रहा है। यह घटनाक्रम झारखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण संकेत देता है।

मुद्दों को धार देने की क्षमता ही असली राजनीतिक ताकत

एक ओर जहां छोटी पार्टियों या एकल विधायकों की सक्रियता उन्हें चर्चा में ला रही है, वहीं बड़े दलों के लिए यह चेतावनी है कि

केवल संख्या बल पर्याप्त नहीं, बल्कि सदन के भीतर प्रभावी उपस्थिति भी जरूरी है। इस घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया

है कि विधानसभा में आवाज उठाने और मुद्दों को धार देने की क्षमता ही असली राजनीतिक ताकत है। टाइगर जयराम महतो

की सक्रियता ने जहां उन्हें केंद्र में ला दिया, वहीं भाजपा के लिए यह आत्ममंथन का विषय बन गया है।

भाजपा के अंदर भी असंतोष उभरा



इस स्थिति को लेकर भाजपा के अंदर भी असंतोष उभरा है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने विधायकों की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई और उन्हें सदन में अधिक आक्रामक और सक्रिय भूमिका निभाने की नसीहत दी। यह फटकार इस बात का संकेत है कि पार्टी नेतृत्व विधानसभा के भीतर अपनी उपस्थिति और

प्रभाव को लेकर गंभीर है। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर भी भाजपा की ओर से कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं लाया गया, जबकि संसदीय परंपरा के अनुसार विपक्षी दल आमतौर पर सरकार को घेरने के लिए इस अवसर का उपयोग करते हैं। इस चूक ने भी भाजपा की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं।

महतो ने सरकार के साथ भाजपा को भी घेरा

सात कटौती प्रस्ताव पेश कर उन्होंने न सिर्फ सरकार को घेरा, बल्कि भाजपा की निष्क्रियता को भी उजागर कर दिया। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विभागों के बजट पर चर्चा के बीच जयराम महतो ने सात कटौती प्रस्ताव पेश किए। इनमें से छह प्रस्तावों पर उन्हें सदन में विस्तार से बोलने का अवसर भी मिला। नियमों के तहत प्रत्येक कटौती प्रस्ताव पर लगभग 15 मिनट बोलने का समय मिलता है, जिसका उन्होंने पूरी तैयारी और आक्रामकता के साथ उपयोग किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, साथ ही विपक्ष की भूमिका पर भी टिप्पणी की।

पंजाब में भाजपा-शिअद में गठबंधन नहीं

- » शाह ने अकेले चुनाव लड़ने के लिए संकेत
- » सुखबीर बोले- स्वागत है

चंडीगढ़। पंजाब अभी चुनाव में एक साल बाकी है। कांग्रेस व आप अभी से तैयारी में जुटी है। इसबीच भाजपा व शिअद में बात नहीं पाई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पंजाब में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के अकेले चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। शाह के इस सियासी संकेतों पर शिअद के अध्यक्ष व पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने तंज कसते हुए प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव में भाजपा का स्वागत है।

मोगा में रैली के दौरान पंजाबियों का सत्कार करने के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पंजाब में फरवरी 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम पंजाब में छोटे भाई के नाते आए



हैं और पंजाबियों के आशीर्वाद से साल 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा यहां सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ने जा रही है। मंच से शाह के इस दावे के बाद चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और भाजपा के गठबंधन की अटकलों को लगभग विराम लग गया है।

सुखबीर का 100 सीटों पर जीत का दावा

इन सियासी संकेतों को समझने के बाद सुखबीर बादल भी थोड़े नाराज दिख रहे हैं। इस पर भाजपा को चुनौती देते हुए सुखबीर ने 100 सीटों पर शिअद की जीत का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि शिअद उसूलों वाली पार्टी है। चुनावी समय में कैसे उतरा है, इस पर फैसला लेना सभी दलों का अपना हम है। लिहाजा हम चुनाव में भाजपा का बतौर प्रतिद्वंद्वी स्वागत करते हैं। शिअद तो लोकसभा में भी अकेले लड़ा था। बादल ने कहा, दिल्ली की पार्टियों को पंजाब और पंजाबियों के हितों से कोई लेना-देना नहीं है, वे तो यहां सिर्फ राज करने आती हैं।

जाखड़, कैप्टन थे गठबंधन के पक्षधर

पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ व पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह दरअसल, चुनाव से पहले शिअद के साथ गठबंधन करने के पक्षधर थे। उनका मानना था कि पहले की तरह अकाली-भाजपा मिलकर सरकार बना सकते हैं मगर भाजपाइयों का एक धड़ा गठबंधन का विरोध कर रहा था। बात हाईकमान तक गई। इसके बाद यह इशारा हो गया था कि इस बार भी भाजपा अकेले दम पर ही पंजाब में चुनाव लड़ेगी और इसीतरह के संकेत अब अमित शाह मोगा रैली में दे गए हैं।

दोनों गठबंधनों ने 2007 से 2017 तक लगातार दो बार सूबे ने सरकार भी बनाई

उधर, शाह के इस सियासी संकेतों पर शिअद के अध्यक्ष व पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने तंज कसते हुए प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव में भाजपा का स्वागत है। पंजाब की सियासत में भाजपा पांव जमाने के लिए लिए लंबे समय से संघर्ष कर रही है। लंबा समय भाजपा ने अकाली

दल के साथ गठबंधन में गुजारा है। इसी गठबंधन ने साल 2007 से 2017 तक लगातार दो बार सूबे ने सरकार भी बनाई। साल 2022 के चुनाव से पहले दोनों दलों की सियासी राह अलग-अलग हो गई थी। पिछले चुनाव में शिअद को भी बड़ा झटका लगा और वे 3 सीटों पर

सिमट गई। अब शिअद आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा से गठबंधन करना चाहती थी। शिअद के नेता यह दावा करते हैं कि पार्टी पंजाब और पंजाबियों के हितों के मुद्दे पर उनसे सहमत होने वाले सियासी दलों से (कांग्रेस व आप को छोड़कर) गठबंधन को तैयार हैं।



Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma

@Editor_Sanjay

जिद... सच की

योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहे

प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीबों को सस्ता और सुलभ आवास उपलब्ध कराना है, लेकिन इसका वास्तविक लाभ सबको नहीं मिल पा रहा है। इसका लाभ तभी मिलेगा जब इसे जमीन पर प्रभावी रूप से लागू किया जाए। यदि योजना केवल कागजों तक सीमित रह जाती है, तो जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिलना मुश्किल होगा। इसलिए जरूरी है कि योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, ताकि हर पात्र व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचे। सस्ते और सुलभ आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ क्रेडिट लिंकड सब्सिडी और आसान होम लोन की सुविधा अहम है। यदि कमजोर और निम्न आय वर्ग को आर्थिक छूट और सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाए, तो वे भी अपना घर बनाने का सपना पूरा कर सकते हैं। इस दिशा में योजनाओं का सरल और व्यापक क्रियान्वयन आवश्यक है। आवास एक मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में निर्माण लागत बढ़ने से सरकारी सहायता अपर्याप्त साबित हो रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि को समय-समय पर बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता और सावधानी जरूरी है, ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को ही इसका लाभ मिल सके। सस्ते आवास सुनिश्चित करने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ानी होगी। किफायती हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जाए, भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित हो और निर्माण लागत कम करने के उपाय किए जाएं। इसके साथ ही, पात्र लोगों को आसान ऋण और सब्सिडी दी जाए, तभी हर व्यक्ति को सम्मानजनक आवास मिल सकेगा। बढ़ते शहरीकरण के बीच सस्ते आवास उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, खासकर प्रवासी श्रमिकों के लिए। राज्य सरकारों को खाली पड़ी जमीनों और अतिक्रमण-मुक्त क्षेत्रों में कम किराये पर आवास उपलब्ध कराने चाहिए। साथ ही, बिल्डरों को निम्न और मध्यम वर्ग के लिए किफायती आवास बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सस्ते आवास के लिए सबसे जरूरी है कि पात्र लोगों की पहचान कर उन्हें किफायती दरों पर भूमि और आसान ऋण उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए नए आवास कल्याण कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं। यदि भूमि और वित्तीय संसाधन सुलभ होंगे, तो अधिक लोग अपने घर बनाने के लिए आगे आएंगे। रैन बसेरों के साथ-साथ आदिवासी और बेघर लोगों के लिए स्थायी आवास की व्यवस्था आवश्यक है।

Sanjay

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

जनभागीदारी व जागरूकता से शुद्ध होगा गंगाजल

ज्ञानेंद्र रावत

गंगा नदी आज भी अपनी शुद्धि की बात जोह रही है। राजीव गांधी के सत्तासीन होने के बाद 1986 में गंगा एक्शन प्लान लागू हुआ था, लेकिन उसके बावजूद गंगा शुद्धि के नाम पर खर्च किए गए हजारों करोड़ रुपये भी उसे प्रदूषण से मुक्त नहीं कर पाए। आज भी गंगा का जल आचमन के लायक नहीं रह गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम पर केंद्रित 2018-2023 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट गंगा की बदहाली को ही दर्शाती है। कैग की रिपोर्ट हाल ही में राज्य विधानसभा के बजट सत्र में पटल पर रखी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, गोमुख से लेकर देवप्रयाग तक गंगा का पानी आचमन योग्य यानी 'ए' श्रेणी का है, जबकि ऋषिकेश और हरिद्वार तक उसका पानी नहाने योग्य यानी 'बी' श्रेणी का है।

कैग रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने गंगातट पर बसे शहरों में सीवेज सुविधाओं में वृद्धि के लिए धन आवंटित नहीं किया। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के डिजाइन में खामियां, इंफ्रास्ट्रक्चर का खराब रखरखाव, गंगा में गिरने वाले नालों को रोकने में नाकामी और नदियों तथा धाराओं में कचरा फेंके जाने पर अंकुश लगाने में असफलताएं रही हैं। कैग की रिपोर्ट में, 'नमामि गंगे' योजना की विफलताएं सामने आई हैं। उदाहरण के लिए, वानिकी हस्तक्षेप का मामला, जिसमें 885.91 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था, परंतु निर्धारित लक्ष्य के विपरीत कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की गई। जिन पेड़ों को लगाने का लक्ष्य था, उनके लिए आवंटित धन का एक भी हिस्सा सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च नहीं किया गया। न तो एसटीपी बने, न ही घरों को सीवर कनेक्शन दिए गए। चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी में 11 श्मशान घाटों का निर्माण हुआ, जो न तो प्रयोग में लाए गए हैं और न ही उनका ठीक से

रखरखाव किया गया है। राज्य के अधिकारियों ने गंगा के संरक्षण के लिए 2020 तक कोई ठोस योजना नहीं बनाई और गंगा में गंदा पानी और औद्योगिक कचरा गिरने से रोकने में नाकामी रही। गंगा किनारे बसे सात शहरों में बने 21 एसटीपी में से एक भी घर का सीवेज इनसे नहीं जुड़ा।

हरिद्वार और ऋषिकेश में ओवरलोडिंग की समस्या तो बढ़ी ही, वहीं जोशीमठ और देवप्रयाग में सीवेज का बहाव भी घट गया। इससे यह साफ है कि एसटीपी अपने उद्देश्य में विफल रहे हैं। गंगा के संरक्षण के लिए जर्मन

भी माना है कि गंगा के 60 फीसदी हिस्से में बिना ट्रीटमेंट के गंदगी गिराई जा रही है। गंगा में सॉलिड और लिक्विड वेस्ट गिरने के कारण और टोटल कोलिफार्म एवं फीकल कोलिफार्म का स्तर अत्यधिक बढ़ गया है। शोधों में यह भी खुलासा हुआ है कि गंगा बेसिन में माइक्रोप्लास्टिक का अत्यधिक प्रसार हो चुका है, जो पारिस्थितिकी तंत्र, जल स्रोतों और जीव-जंतुओं के लिए भी गंभीर खतरा है। माइक्रोप्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होता और पर्यावरण में जमा हो जाता है, जो समुद्री तंत्र और प्राणी जगत के लिए भी एक भयंकर



डेवलपमेंट बैंक जैसी संस्थाओं द्वारा दिया गया फंड भी सिर्फ हरिद्वार और ऋषिकेश तक ही सीमित रहा। ऋषिकेश के ढालवाला, कीर्तिनगर, रुद्रप्रयाग, श्रीकोट, गोपेश्वर और कर्णप्रयाग जैसे स्थानों पर 12 एसटीपी बिना ट्रीट किए गंदा पानी गंगा में बहा रहे हैं। 44 एसटीपी में से 8 एसटीपी चार साल से अधिक समय तक बिना पीसीबी की मंजूरी के संचालित हो रहे हैं। 18 एसटीपी अभी तक उत्तराखंड जल संस्थान को सौंपे ही नहीं गए हैं। ये सभी गंगा की शुद्धि के लिए बनी योजनाओं की नाकामी के प्रतीक हैं। गंगा की यह बदहाली जब उत्तराखंड में है, तो उसके बहाव क्षेत्र जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में तो स्थिति का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। गंगा के बहाव क्षेत्र के अधिकांश स्थानों पर कोलिफार्म बैक्टीरिया की मात्रा मानक से 45 गुणा से भी अधिक पाई गई है। एनजीटी ने

समस्या है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के शोध में यह पाया गया कि गंगा किनारे के प्रदूषित इलाकों में प्रदूषण बढ़ने से लोगों की उम्र कम हो गई है।

एंटीबायोटिक्स के बेअसर होने के कारण बैक्टीरिया होने से हर साल सात लाख मौतें होती हैं। धार्मिक कारणों से लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हैं और उसका जल आचमन करते हैं। इसके कारण गंगाजल में घुले एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया उनके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। गंगा शुद्धिकरण के अभियान में केंद्र सरकार के सात मंत्रालयों की साख दांव पर है। असल में, गंगा तब तक शुद्ध नहीं हो सकती जब तक स्थानीय निकाय ईमानदारी से अपनी भूमिका का निर्वहन न करें और इस अभियान में जनभागीदारी को अहमियत न दी जाए। सबसे महत्वपूर्ण सवाल देश की धर्मपरायण जनता की जागरूकता का है।

विश्वनाथ सचदेव

देश के पांच राज्यों में चुनावों की घोषणा हो गयी है। अब चुनाव-प्रचार में तेजी आयेगी। इस तेजी का एक मतलब नेताओं के भाषणों में तेजी आना है। वैसे भी, हमारे नेता, चाहे वे किसी भी दल वाले हों, बोलने में किसी से पीछे नहीं हैं, पर अब यह बड़बोलापन और उभर कर सामने आयेगा। हमारे नेता कभी भी, कहीं भी, कुछ भी बोल सकते हैं। ताजा उदाहरण असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा हैं। एक समाचार-चैनल के कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने घोषणा कर दी है कि वर्ष 2031 तक वे असम के सभी कांग्रेसी नेताओं को अपने दल, यानी भाजपा, में समाहित कर लेंगे। यह कहकर वे बताना चाहते थे कि अगले पांच साल में, वे असम राज्य को कांग्रेस-विहीन बना देंगे। दस साल पहले कुछ ऐसा ही नारा भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी दिया था-वे देश को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते थे।

वैसे उन्हें अधिकार है अपनी बात को अपने ढंग से समझाने का, पर सामान्य समझ यह बताती है कि इन नेताओं का लक्ष्य या उद्देश्य देश की राजनीति को एकदलीय बनाना है। हमारे जनतंत्र में ऐसा होना न तो वांछित है, न ही संभव, पर ऐसा इरादा रखनेवालों को कौन रोक सकता है? हमारा भारत बहुत बड़ा देश है। आसेतु-हिमालय यहाँ अनेक धर्म हैं, अनेक विचारधाराएं हैं। देश के हर नागरिक को अधिकार है अपनी बात कहने, अपनी बात समझाने का, अपनी विचारधारा के प्रचार-प्रसार का। हर नागरिक को यह भी अधिकार है कि वह दूसरे को गलत सिद्ध करने की कोशिश करे। शर्त बस यह है कि वह यह काम तार्किक

चुनावों में संयम समझदारी दिखाएं राजनेता

ढंग से, विवेकशील तरीके से करे-- यह सब करते हुए दूसरे के इस अधिकार को भी स्वीकारे कि उसे भी अपनी बात कहने का उतना ही अधिकार है। बात सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की नहीं है, बात एक ऐसी व्यवस्था को भी स्वीकारने की है जिसे हमने अपने लिए चुना है। हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था में अलग-अलग विचारों को रहने-पनपने के अवसर हैं। हर रंग के फूल खिलें, हर फूल की अपनी गंध हो।

रंग और गंध की यह विभिन्नता हमारे बगीचे का सौंदर्य है और यह विभिन्नता हमारी ताकत भी है। बनी रहनी चाहिए यह विभिन्नता, ताकि हमारी ताकत भी बनी रहे। देश में एकता का मतलब यह है कि विभिन्न धर्मों, जातियों, वर्गों का होने के बावजूद हमारे भीतर यह अहसास बना रहे कि हम सब इस देश के नागरिक हैं, देश के हित में ही हम सबका हित निहित है। इसका मतलब यह भी है कि विभिन्न विचारधाराओं का मतलब यह नहीं है कि हम एक-दूसरे के दुश्मन हैं। हम एक-दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, एक-दूसरे को गलत मान सकते हैं, बता सकते हैं। पर हम यह कदापि नहीं चाहेंगे



कि दूसरे की कीमत पर हम अपना हित साधें। हमें एकता और एकरूपता के अंतर को पहचानना होगा। एकरूपता चाहने का मतलब है दूसरे के अस्तित्व को नकारने की कोशिश करना, जबकि एकता हमें साथ मिलकर आगे बढ़ने का अवसर देती है, अर्थ समझाती है। एकता हमें बताती है कि हमारा हित एक-दूसरे के साथ होने, साथ जीने में है, जबकि एकात्मकता का अर्थ है भिन्नता का मिट जाना।

किसी अस्तित्व का इस तरह का नकार आध्यात्मिक अर्थों में भले ही आकर्षक लगता हो, पर लौकिक जीवन में यह अद्वैत' समस्याओं को जन्म देने वाला ही हो सकता है। आओ, साथ जियें, और मेरे साथ जीने के लिए तुम मिट जाओ के अंतर को हमें समझना होगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी विचारधारा का हो, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। पर वह इसलिए अच्छा या बुरा नहीं है कि वह किसी धर्म या किसी विचारधारा को मानता है। विभिन्न विचारों, धर्मों का होने के बावजूद हम साथ रह सकते हैं, यह साथ

रहना ही हमारी एकता है। एक-दूसरे को अपना मानना हमारी ताकत है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, जहाँ इतने सारे धर्म मिल-जुलकर रह रहे हैं, पनप रहे हैं। लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि अपने धर्म के प्रसार के नाम पर कोई दूसरे धर्म के प्रति नफरत का भाव फैलाये। अपने धर्म की विशेषताओं को बताने-समझाने का मेरा अधिकार मुझे यह अधिकार नहीं देता कि मैं दूसरे के धर्म के प्रति अनुचित शब्दों का इस्तेमाल करूँ अथवा गलत भावनाएं फैलाऊँ।

बहरहाल, यह एक दुखद स्थिति है कि आज देश में राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए धर्म के नाम पर अनुचित माहौल बनाया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री ने जब राज्य के सारे कांग्रेसियों को भाजपाई बनाने वाली बात कही थी तो उन्होंने एक को छोड़कर शब्दों का इस्तेमाल भी किया था। उनका स्पष्ट इशारा किसी अल्पसंख्यक नेता की ओर था। धर्म-विशेष का नाम लेकर सांप्रदायिकता को हवा देने वाले इस तरह के विचार-व्यवहार के लिए जनतांत्रिक भारत में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य की बात तो यह भी है कि धर्म के नाम पर यह वैमनस्य-भाव फैलाने की प्रवृत्ति सड़क से लेकर संसद तक फैलती दिख रही है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए हमारे कुछ सांसद इस संदर्भ में आपराधिक प्रवृत्ति का परिचय दे रहे हैं। यह प्रवृत्ति घातक है, और खतरनाक भी। यह भी कम बड़ी त्रासदी नहीं है कि हमारे नेता, विधायक से लेकर मंत्री तक, खुलेआम साम्प्रदायिकता फैलाने की बातें कर रहे हैं। अलीगढ़ के एक सांसद, महाराष्ट्र के एक मंत्री और एक केंद्रीय मंत्री के हालिया बयान चौंकाने वाले भी हैं, और डरावने भी। यह प्रवृत्ति रुकनी ही चाहिए।

पीठ और कंधे की चर्बी

हटाने के लिए करें ये योगासन

आज की लाइफस्टाइल जैसे लंबे समय तक कुर्सी पर बैठना, मोबाइल-लैपटॉप पर झुकी हुई गर्दन और शारीरिक निष्क्रियता पीठ और कंधों की चर्बी बढ़ाने की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। यह चर्बी न सिर्फ दिखने में खराब लगती है, बल्कि दर्द, अकड़न और पोस्चर की समस्या भी पैदा करती है। इसे बिना जिम जाए, बिना भारी एक्सरसाइज किए योग से पीठ व कंधे की चर्बी को कम किया जा सकता है। इसके लिए बस नियमितता और सही तरीका चाहिए। कई तरह की शारीरिक गतिविधियां आपके द्वारा बढ़ाई गई कैलोरी को जलाकर वजन घटाने में आपकी मदद कर सकती हैं। आपके कमर और कंधे में अगर जिद्दी चर्बी जम गई है तो फिर आपको यहां पर कुछ आसान एक्सरसाइज हैं जिससे आप आसानी से गलाकर एक परफेक्ट फीगर पा सकते हैं। ये योगासन बैक फैट, शोल्डर फैट और अपर-बैक टोनिंग के लिए खास तौर पर कारगर हैं। इसके अलावा वजन घटाने के लिए पैदल

चलना सबसे अच्छे व्यायामों में से एक है।



धनुरासन

यह आसन पूरे बैक एरिया को एक्टिव करता है और फेट बर्न में मदद करता है। इसे करने के लिए पेट के बल लेटकर घुटनों को मोड़ें अब हाथों से टखने पकड़ें फिर शरीर को धनुष की तरह ऊपर उठाएं। इसे करने से बैक फैट तेजी से कम होता है, शरीर की शोप सुधरती है, मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। यह आसन चिंता और अवसाद जैसी मानसिक परेशानियों को दूर करने के लिए धनुरासन का नियमित अभ्यास बहुत फायदेमंद है। कई शोध और अध्ययन इस बात की पुष्टि हुई है की धनुरासन या बो पोज का अभ्यास करने से शरीर में मौजूद स्ट्रेस हॉर्मोन कम होता है और मानसिक समस्याओं में फायदा मिलता है।

गोमुखासन

यह आसन खास तौर पर कंधों और अपर बैक के लिए बेहद असरदार है। इसे करने के लिए एक हाथ ऊपर से और दूसरा नीचे से पीछे ले जाएं फिर दोनों हाथों की उंगलियां पकड़ें। इसे करने से शोल्डर फैट कम होता है और हाथ-कंधों की शोप सुधरती है और जमी हुई चर्बी पर इसका असर पड़ता है। गोमुखासन पेट के तनाव को दूर करने और पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। यह पेट की मांसपेशियों को फैलाता है, उनके कार्य की क्षमता को बढ़ाता है और पेट में होने वाली असुविधाओं को कम करने में फायदेमंद है।



अधोमुख श्वानासन

यह आसन कंधों और पीठ के ऊपरी हिस्से पर बेहतरीन काम करता है। इसे करने के लिए हाथ और पैर जमीन पर टिकाएं, शरीर को उल्टे आकार में लाएं फिर एड़ियां नीचे की ओर दबाएं। इसे करने से शोल्डर फैट कम होता है, पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है।

सेतुबंधासन

यह आसन पीठ के निचले और ऊपरी हिस्से दोनों को टोन करता है। इसे करने के लिए पीठ के बल लेटें और अपने घुटनों को मोड़ें, और फिर पैर जमीन पर रखते हुए कमर को ऊपर उठाएं। इसे करने से बैक फैट घटाने में मदद मिलती है। रीढ़ मजबूत होती है और थकान कम होती है। यह आसन पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां ब्लैडर कंट्रोल करने, मल त्याग करने और सेक्सुअल परफॉर्मेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस योगासन को करने से पेल्विक फ्लोर को मजबूत करने के साथ कोर स्थिरता और सहनशक्ति में सुधार करता है, जो शारीरिक गतिविधियों और उम्र के साथ होने वाली समस्याओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भुजंगासन

यह आसन रीढ़ को मजबूत करता है और अपर बैक की चर्बी पर सीधा असर डालता है। इसे करने के लिए पेट के बल लेट जाएं, हथेलियां कंधों के नीचे रखें और सांस लेते हुए छाती ऊपर उठाएं, इस अवस्था में 15-20 सेकंड रुकें, फिर सामान्य स्थिति में आएं। इस योगासन को करने से पीठ की चर्बी कम होती है, कमर दर्द में राहत मिलती है आर रीढ़ लचीली बनती है।



हंसना मना है

रुपेश : पापा मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ.. पापा: क्या वो भी तुझे पसन्द करती है? रुपेश : हां जी हां.. पापा: जिस लड़की की पसन्द ऐसी हो, मैं उसे अपनी बहू नहीं बना सकता।

सरदार दुखी था। किसी ने पुछा: क्यों टेंशन में हो? सरदार: यार एक दोस्त को प्लास्टिक सर्जरी के लिए 2 लाख दिए, अब साले को पहचान नहीं पा रहा हूँ।

संता अपनी बीमारी की वजह से डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर: आपकी बीमारी की सही वजह मेरी समझ में नहीं आ रही, हो सकता है दारु पीने की वजह से ऐसा हो रहा हो, संता: कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, जब आपकी उतर जाएगी तो मैं दोबारा आ जाऊंगा।

पापा और 15 साल का बेटा एक होटल में गए, पापा- वेटर एक बियर और एक आईसक्रीम लाओ, बेटा- आईसक्रीम क्यों पापा, आप भी बियर लीजिये ना, दे.. चप्पल.. पे.. चप्पल!

पत्नी- जरा किचन से आलू लेते आना। पति- यहां तो कहीं आलू दिख नहीं रहे हैं। पत्नी- तुम तो हो ही अंधे, कामचोर हो। एक काम ढंग से नहीं कर सकते, मुझे पता था कि तुम्हें नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं पहले ही ले आई थी!

कहानी | क्रोधित राजा और ऋषि

ढोलकपुर साम्राज्य में एक ऋषि रहते थे, जो लोगों का भाग्य बताते थे। एक दिन राजा के मन में भी भविष्य जानने की इच्छा हुई। उन्होंने ऋषि को पूरे सादर-सम्मान से महल आने का आमंत्रण दिया। ऋषि सैनिकों के साथ महल चलने के लिए तैयार हो गए। जब ऋषि महल पहुंचे, तो राजा ने बड़े ही उत्साह से उनका स्वागत-सत्कार किया और उन्हें अपने दरबार में सम्मान के साथ बैठाया। राजा ने ऋषि के सामने अपने मन की इच्छा रखी और उनसे अपने भविष्य के बारे में पूछा। ऋषि ने राजा से उसकी जन्मकुंडली मंगाई और उसे ध्यान से देखने लगे। ऋषि ने राजा को बताया कि भविष्य में उनका भाग्य आशीर्वाद भरा हुआ है और जीवन में सबकुछ अच्छा ही होगा। राजा खुद से जुड़ी अच्छी भविष्यवाणी सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने खुश होकर ऋषि को सोने और चांदी का उपहार दिया। फिर उसने भविष्य से जुड़े दुर्भाग्य के बारे में पूछा। ऋषि ने राजा के दुर्भाग्य से जुड़ी बातें भी बता दीं। उन्हें सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गया। वह गुस्से में ऋषि पर चिल्लाने लगा और कहा कि अब मुझे मेरी मृत्यु का समय बताओ। ऋषि समझ चुका था कि राजा अपना दुर्भाग्य सुनकर उसपर क्रोधित हो गया है। राजा की मृत्यु वाली बात सुनते ही वह शांति से कुछ गणना करने लगा। इसके बाद शांत स्वर में कहा कि मेरी गणना और कौशल के अनुसार, आपकी मृत्यु मेरी मृत्यु के ठीक एक घंटे बाद होगी। राजा ऋषि की यह बात सुनकर हैरान हो गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने तुरंत अपनी तलवार नीचे रखी और ऋषि के साथ किए गए अपने दुर्व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगी। बाद में राजा ने ऋषि को ढेर सारा धन दिया और उन्हें वापस कुटिया में आदर व सम्मान के साथ भेज दिया।

7 अंतर खोजें



जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951



पंडित संदीप आनंद शर्मा

मेघ 	कुबुद्धि हावी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विवाद से दूर रहें। कुसंगति से बचें। भूमि व भवन संबंधी बाधा दूर होगी। बड़े सौदे बड़ा लाभ दे सकते हैं। आय में वृद्धि होगी।	तुला 	व्यापार-व्यवसाय अच्छा चलेगा। शत्रु शांत रहेंगे। ऐश्वर्य पर खर्च होगा। मान-सम्मान मिलेगा। अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे। कर्ज लेना पड़ सकता है।
वृषभ 	मान-सम्मान मिलेगा। यात्रा मनोरंजक रहेगी। किसी मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग सफलता प्राप्त करेगा। समय अनुकूल है।	वृश्चिक 	प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। शुभ समाचार मिल सकता है। शारीरिक कष्ट संभव है। अज्ञात भय रहेगा। लेन-देन में सावधानी रखें। चिंता रहेगी।
मिथुन 	वर्ध भागदौड़ रहेगी। समय का अपव्यय होगा। दूर से दुःखद समाचार प्राप्त हो सकता है। विवाद से वलेश होगा। काम में मन नहीं लगेगा। लेन-देन में जल्दबाजी न करें।	धनु 	आराम का समय मिलेगा। आशंका-कुशंका रहेगी। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। नई योजना बनेगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। प्रमाद न करें।
कर्क 	कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। शारीरिक कष्ट संभव है। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि नीचा देखना पड़े।	मकर 	यात्रा मनोनुकूल लाभ देगी। राजभय रहेगा। जल्दबाजी व विवाद करने से बचें। थकान महसूस होगी। किसी के व्यवहार से स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है। आय में वृद्धि होगी।
सिंह 	शत्रु शांत रहेंगे। वाणी पर नियंत्रण रखें। दूर से शुभ समाचार प्राप्त होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। घर में प्रतिष्ठित अतिथियों का आगमन हो सकता है। व्यय होगा।	कुम्भ 	आज मान-सम्मान के योग बनेंगे। वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। शारीरिक शिथिलता रहेगी। काम में मन नहीं लगेगा।
कन्या 	भाग्यजति के प्रयास सफल रहेंगे। रोजगार प्राप्ति सहज ही होगी। व्यावसायिक यात्रा से लाभ होगा। अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। निवेशादि शुभ रहेंगे।	मीन 	कष्ट, भय व चिंता का वातावरण बन सकता है। विवेक से कार्य करें। समस्या दूर होगी। कानूनी अडचन दूर होकर स्थिति मनोनुकूल बनेगी। धनार्जन होगा।

फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर वामिका गब्बी काफी उत्साहित हैं। इस फिल्म में वह बिल्कुल ही अलग अंदाज में दर्शकों से रूबरू होंगी। हाल ही में फिल्म से जुड़ी एक अपडेट सामने आई, जिससे पता चलता है कि एक्ट्रेस खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार से काफी इंस्पायर है। वह उनके नक्शे-कदमों पर चल रही हैं।

सूत्रों के अनुसार फिल्म 'भूत बंगला' में वामिका गब्बी ने अपने एक्शन सीन खुद किए हैं। एक्ट्रेस ने एक ट्रेन सीकेंस शूट किया, जिसमें वह ट्रेन के किनारे पर खड़ी थीं। इस सीन के लिए अक्षय कुमार के साथ एकदम सही तालमेल और टाइमिंग की जरूरत थी। वामिका ने अक्षय कुमार का पूरा साथ दिया।

फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि वामिका को इस सीन के लिए अक्षय पर पूरा भरोसा था। उन्होंने बिना किसी एक्सट्रा सपोर्ट के सीन किया।

पिछले दिनों फिल्म 'भूत बंगला'

वामिका गब्बी ने भूत बंगला के सेट पर जीता सबका दिल

बॉलीवुड

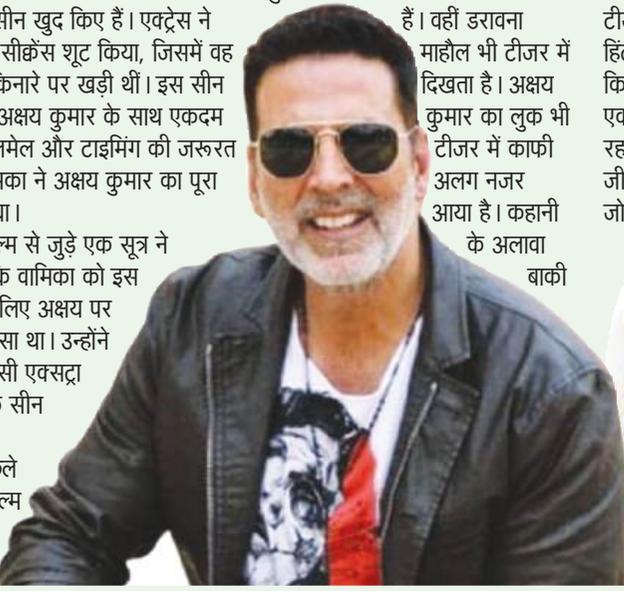
मसाला

का टीजर रिलीज हुआ। इसमें अक्षय कुमार जहां अपनी कॉमेडी से हंसाते हैं। वहीं डरावना माहौल भी टीजर में दिखता है। अक्षय कुमार का लुक भी टीजर में काफी अलग नजर आया है। कहानी के अलावा बाकी

कलाकारों की भी झलक भी टीजर में दिखती है, इसमें वामिका भी नजर आई। टीजर से ही हिंट मिला है कि इसमें एक रहस्यमयी जीव है जो

सबको डराता है।

फिल्म 'भूत बंगला' में अक्षय कुमार, वामिका गब्बी के अलावा परेश रावल, तब्बू और राजपाल यादव भी हैं। यह फिल्म 10 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में असरानी की भी झलक मिलेगी। पिछले साल इस दिग्गज अभिनेता ने दुनिया को अलविदा कह दिया था।



फिलहाल अभी टल गई सलमान खान की मातृभूमि की रिलीज डेट

शा सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवा' जिसका नाम बदलकर अब 'मातृभूमि' हो गया है, पहले अप्रैल में रिलीज होने वाली थी। लेकिन अब ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव के कारण फिल्म की रिलीज टल गई है। रिलीज में देरी का एक मुख्य कारण अभिनेता-गायक प्रशांत तमांग का असमय निधन भी बताया जा रहा है।

फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि इंडियन आइडल 3 के विजेता प्रशांत तमांग 'मातृभूमि' में मेन विलेन



की भूमिका निभाने वाले थे। उन्होंने कई अहम सीन की शूटिंग भी कर ली थी। हालांकि, जनवरी में उनके निधन के समय कुछ महत्वपूर्ण सीन की

शूटिंग बाकी थी। टीम के पास कुछ निर्धारित शेड्यूल थे, जिनमें प्रशांत को कुछ बेहद जरूरी सीन की शूटिंग करनी थी। लेकिन उनके निधन से अब

फिल्म की टीम के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। हालांकि, मेकर्स ने पहले प्रशांत के सीन की दोबारा शूटिंग करने पर विचार किया था, लेकिन फिलहाल यह संभव नहीं लगता। सूत्र ने बताया कि क्लोज-अप शॉट्स तो लिए जा सकते हैं, लेकिन वह कई एक्शन सीन का भी हिस्सा थे। यह न केवल आर्थिक रूप से अव्यवहारिक होगा, बल्कि व्यवस्था के लिहाज से भी एक बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा सलमान खान की डेट्स की उपलब्धता और उनके लुक की निरंतरता भी चुनौतियों को बढ़ा रही है।

बॉलीवुड

मन की बात

सिर्फ एक ही सिनेमा यानी भारतीय सिनेमा होना चाहिए : कमल हासन



बी

ते दिन तेलंगाना गद्दर फिल्म अवॉर्ड्स 2025 आयोजित हुए। यहां भारतीय सिनेमा के कई सितारे पहुंचे। कुछ को सम्मानित भी किया गया। अवॉर्ड नाइट में दिग्गज अभिनेता कमल हासन और मेगा स्टार चिरंजीवी को भी पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी दौरान दोनों सितारों ने इस बात पर जोर दिया कि देश में क्षेत्रीय सिनेमा की बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक ही सिनेमा यानी भारतीय सिनेमा होना चाहिए। तेलंगाना गद्दर फिल्म अवॉर्ड्स 2025 में कमल हासन ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से भारत की क्षेत्रीय फिल्म इंडस्ट्रीज के बीच की सीमाओं को खत्म करने की अपील की। वहीं, चिरंजीवी ने हैदराबाद को देश का सिनेमा का हब बनाने का अपना विजन पेश किया। बता दें कि बीती रात दोनों दिग्गज सितारों को सम्मानित किया गया। कमल हासन को इस अवॉर्ड फंक्शन में पैडी जयराज फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं, मेगास्टार चिरंजीवी को एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद दोनों सितारों ने मंच से कुछ ऐसा कहा, जिसकी इंडस्ट्री को काफी समय से जरूरत थी। कमल हासन और चिरंजीवी, दोनों सितारों का अभिनय करियर काफी लंबा है। दोनों ने 70 के दशक में काम शुरू किया था और उनके पीछे 50 साल का शानदार करियर है। उन्होंने एक ही दशक में शुरुआत की। कमल हासन को इस अवॉर्ड फंक्शन सम्मान प्राप्त करने के बाद अपने संबोधन में सबसे पहले चिरंजीवी के साथ अपने रिश्ते के बारे में कुछ ऐसा कहा, जिससे पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूँज उठा। उन्होंने कहा, चिरंजीवी और मैं भाई हैं। वे राजनीति में मुझसे सीनियर हैं, लेकिन एक्टिंग में जूनियर हैं। उनकी इस बात पर पूरा हॉल ठहाकों से गूँज उठा। उन्होंने आगे कहा, हम दोनों ने 70 के दशक में एक्टिंग शुरू की थी और अब हम दोनों ही 70 साल के हो चुके हैं।

पियाव कड़ कर्मचारी को कंपनी ने बाहर निकाला तो अदालत ने दिया अजीब फैसला

काम के दौरान नशा करना या शराब पीना किसी भी कंपनी में गंभीर अनुशासनहीनता मानी जाती है। इसके लिए कर्मचारी को तुरंत नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन स्पेन के मर्सिया से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने दुनिया भर के कॉर्पोरेट जगत को हैरान कर दिया है। यहां एक इलेक्ट्रिकल कंपनी में काम करने वाले शख्स को इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि वह ड्यूटी के दौरान भारी मात्रा में बीयर पीता था। कंपनी ने सबूत के तौर पर प्राइवेट जासूस तक लगाए, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह शख्स एक दिन में करीब 3 लीटर बीयर गटक जाता था। लेकिन जब यह मामला कोर्ट पहुंचा, तो जज ने जो फैसला सुनाया उसने कंपनी के होश उड़ा दिए। कोर्ट ने न केवल कर्मचारी की बर्खास्तगी को गलत बताया, बल्कि कंपनी को उसे 47,000 यूरो (करीब 50 लाख रुपये) का हर्जाना देने का भी आदेश दिया। इस कानूनी लड़ाई की शुरुआत तब हुई जब कंपनी को अपने एक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वर्कर के व्यवहार पर शक हुआ। कंपनी ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव को काम पर रखा। जासूस ने कई दिनों तक उस शख्स का पीछा किया और एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वह शख्स पार्किंग लॉट्स और बार में जाकर बीयर पीता था। एक दिन तो उसने अपने लंच ब्रेक के दौरान ही 3 लीटर बीयर पी ली थी। यह एक बहुत ही गंभीर मामला था, क्योंकि वह कर्मचारी कंपनी की गाड़ी भी चलाता था। इस बारे में कंपनी का कहना था कि उसकी शराब पीने की आदत न केवल काम को प्रभावित कर रही थी, बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रही थी, क्योंकि वह गाड़ी भी चलाता था। इसी आधार पर उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया। हैरानी की बात यह है कि कर्मचारी ने अपनी गलती मानने के बजाय कंपनी पर गलत तरीके से निकालने का मुकदमा टोक दिया। 'हाईकोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ मर्सिया' में चली सुनवाई के दौरान जजों ने माना कि कर्मचारी का व्यवहार अनुचित था, लेकिन कंपनी द्वारा दी गई सजा बहुत ज्यादा सख्त थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी के पास दो ही विकल्प हैं, पहला यह कि या तो वे उस शख्स को दोबारा नौकरी पर रख लें और दूसरा यह कि फिर उसे करीब 50 लाख रुपये का मुआवजा दें। स्पेनिश कोर्ट ने इस फैसले के पीछे कई दिलचस्प तर्क दिए। जजों का मानना था कि लंच ब्रेक को तकनीकी रूप से 'वर्किंग आवर्स' यानी काम का समय नहीं माना जा सकता। इसलिए, उस दौरान पी गई बीयर को औपचारिक रूप से काम से जुड़ी अनुशासनहीनता नहीं कहा जा सकता।



अजब-गजब ये जगह जितनी ही खूबसूरत है उतनी ही डरावनी

खूबसूरत वादियों में छिपा है यमदूत कुत्ता, कुचलकर मार देता है इंसानों को, जाने के नाम से भी कांपते हैं लोग!

दुनियाभर में ऐसी कई जगहें हैं, जिनके बारे में सुनकर एक अजीब सा रोमांच और डर दोनों एक साथ महसूस होता है। कहीं लोग एलियंस के होने का दावा करते हैं, तो कहीं ऐसी पहाड़ियां हैं जहां गाड़ियां बिना इंजन के खुद-ब-खुद ऊपर चढ़ने लगती हैं। लेकिन आज हम आपको इंग्लैंड के एक ऐसे रहस्यमयी ठिकाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जो पहली नजर में जितना खूबसूरत लगता है, उसकी कहानी उतनी ही डरावनी है। उस रहस्यमयी जगह का नाम ट्रोल्स गिल है, जो इंग्लैंड के यॉर्कशायर के वॉर्फेडेल इलाके में है। देखने में यह जगह किसी फिल्मी लोकेशन से कम नहीं लगता। ऊंची-ऊंची चट्टानें, हरियाली और बीच से बहता झरना-सब कुछ इतना सुकून देने वाला है कि यहां आने वाला हर शख्स खुद को प्रकृति के बेहद करीब महसूस करता है। लेकिन जैसे-जैसे आप इस घाटी के अंदर बढ़ते हैं, माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा और अनजाना डर महसूस होने लगता है। स्थानीय लोगों की मानें तो यह खामोशी घाटी देखने में जितनी खूबसूरत है, उतनी ही ज्यादा डरावनी यहां से जुड़ी एक खौफनाक कहानी भी है। यह कहानी है एक ऐसे रहस्यमयी कुत्ते की, जिसे वे 'बरगेस्ट' कहते हैं। कहा जाता है कि यह कोई आम जानवर नहीं, बल्कि



एक डरावना दैत्याकार कुत्ता है। इसकी आंखें अंगारों की तरह जलती हैं और जो भी इसे देख ले, समझो उसकी मौत निश्चित है। कई लोग इस कुत्ते की तुलना यमदूत से करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सड़क के बिल्कुल पास होने के बावजूद यह जगह आसानी से नजर भी नहीं आती। अगर आपको रास्ता नहीं पता है, तो आप यहां नहीं पहुंच सकते हैं। करीब 2.6 किलोमीटर का यह ट्रैक एडवेंचर पसंद लोगों के लिए किसी छिपे खजाने जैसा है। रास्ते में चट्टानों के बीच से अचानक गिरता पानी और बीच में पड़ने वाली पुरानी 'गिल हेड्स माइन', जो अब वीरान और खतरनाक हालत में है। यहां के लोगों के बीच एक पुरानी कहानी आज भी सुनाई जाती है। कहते हैं कि जॉन लैम्बर्ट नाम के एक

शख्स ने नशे में इस रहस्यमयी कुत्ते को चुनौती दी थी, जो अगली सुबह पहाड़ी के नीचे मृत पाया गया। हालांकि, इस कहानी का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन आज भी इसे यहां के लोग सच मानते हैं। इतना ही नहीं, 19वीं सदी की एक कविता में भी एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र मिलता है, जिसने जादुई घेरा बनाकर इस कुत्ते को बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन वह भी खुद को बचा नहीं पाया। इस घाटी का नाम ट्रोल्स पर पड़ा है, जो स्कैंडिनेवियाई संस्कृति में शापित या जादू-टोने से जुड़ी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। पुराने समय में यहां रहने वाले लोग मानते थे कि यह जगह शापित है और यहां अदृश्य शक्तियों का वास है। हालांकि, आज भी जो लोग यहां ट्रैकिंग के लिए आते हैं, उनमें से कई दावा करते हैं कि उन्हें चट्टानों के पीछे से किसी के चलने या भारी सांस लेने जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। सच क्या है, यह कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि यहां कदम रखते ही आपको एहसास हो जाता है कि यह सिर्फ एक खूबसूरत घाटी नहीं, बल्कि रहस्यों से भरी एक अलग ही दुनिया है। प्रकृति की गोद में बसी यह जगह आज भी उन लोगों को अपनी ओर खींचती है, जो रोमांच के साथ-साथ अनजाने डर को महसूस करना चाहते हैं।

संजय राउत के किताब से सियासी घमासान

» राउत बोले- ईडी के दबाव में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पद छोड़ा था

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। संजय राउत का दावा है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 2025 में दबाव के चलते पद छोड़ा था। ये दावे उन्होंने अपनी किताब में बताया है। उनकी इस किताब के बाजार में आने के बाद सियासी संग्राम आरंभ हो गया है। जहां विपक्ष ने भाजपा सरकार को घेर लिया है वहीं भाजपा तिलमिला गई है। अपनी किताब अनलाइकली पैराडाइस के जरिए उन्होंने कई ऐसे विस्फोटक दावे किए हैं, जिन्हें लेकर राजनीतिक हलकों में सनसनी फैलाने की कोशिश साफ नजर आती है। यह किताब आरोपों, संकेतों और सवालों का ऐसा मिश्रण पेश करती है, जो सीधे तौर पर सत्ता, जांच एजेंसियों और लोकतंत्र के रिश्ते पर उंगली उठाती है।

बता दें संजय राउत का सबसे बड़ा दावा यह है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 2025 में दबाव के चलते पद छोड़ा था। उनके मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय यानि ईडी ने कथित तौर पर एक फाइल तैयार की थी, जिसे धनखड़ के सामने तब रखा गया जब उन्होंने सरकार के खिलाफ स्वतंत्र राजनीतिक रुख अपनाने के संकेत दिए थे। हालांकि इन दावों की

विपक्ष ने सरकार को घेरा, भाजपा तिलमिलाई

पूर्व चुनाव आयुक्त को लेकर भी किताब में गंभीर आरोप

यही नहीं, पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को लेकर भी किताब में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। संजय राउत का कहना है कि जब लवासा ने आचार संहिता उल्लंघन के

मामलों में असहमति जताई, तो उनके खिलाफ जांच और दबाव की कार्रवाई शुरू हुई। दावा किया गया है कि उनके घर पर छापे पड़े और परिवार को समन भेजे गए, जिसके

बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा। हालांकि इन दावों पर भी आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन यह मामला संस्थाओं की स्वतंत्रता पर बहस को फिर से जिंदा कर देता है।

जेल में बंद रहने के दौरान उनके अनुभवों पर आधारित है पुस्तक

कदम से पूरा देश हतप्रभ रह गया था। हम आपको यह भी याद दिला दें कि संजय राउत को ईडी ने

2022 में धनशोधन से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया था। शिवसेना (यूबीटी) नेता ने जमानत पर रिहा होने के बाद मुंबई की आर्थर रोड जेल में अपने अनुभवों पर मराठी में 'नरकटला स्वर्ग' नाम से किताब लिखी जो पिछले साल प्रकाशित हुई थी। संजय राउत ने विस्तृत जानकारी दिये बिना बताया, "संशोधित (अंग्रेजी) संस्करण में धनखड़ पर एक अध्याय है। केंद्रीय एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों के पांच-छह और उदाहरण हैं।" इस पुस्तक 'अनलाइकली पैराडाइस' का विमोचन 23 मार्च को यानि आज नयी दिल्ली में होगा। किताब का विमोचन राज्यसभा सदस्य कपिल सिबल, संजय सिंह, डेरेक ओ'ब्रायन और जया बच्चन करेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पुस्तक विमोचन समारोह में शामिल होंगे।



मोदी को जेल भेजने की चर्चा के दौरान शरद पवार ने विरोध किया था

किताब में अतीत के कुछ राजनीतिक प्रसंगों का भी जिक्र है। संजय राउत के अनुसार, गुजरात दंगों के बाद उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल भेजने की चर्चा के दौरान शरद पवार ने इसका विरोध किया था। उनका तर्क था कि लोकतांत्रिक रूप से चुने गए मुख्यमंत्री को राजनीतिक मतभेद के कारण जेल भेजना उचित नहीं है। यह दावा भी अपने आप में राजनीतिक नैतिकता और फैसलों की दिशा को लेकर सवाल उठाता है।



शाह को जमानत दिलाने में शरद पवार और बाल ठाकरे की भूमिका थी

यही नहीं, अमित शाह से जुड़ा एक दावा भी किताब में सामने आया है। इसमें कहा गया है कि उन्हें जमानत दिलाने में शरद पवार और बाल ठाकरे की भूमिका रही थी, जबकि जांच एजेंसी इसका विरोध कर रही थी। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया है कि अमित शाह ने खुद बाल ठाकरे से मदद मांगी थी और एक हस्तक्षेप ने उनके राजनीतिक भविष्य को बदल दिया। इन दावों की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह सियासत के अंदरूनी समीकरणों की झलक जरूर दिखाते हैं।



पीएम मोदी खुद घुसपैटिया : ममता

» टीएमसी प्रमुख बोलीं- बाहर जाकर मुस्लिम देशों से दोस्ती, देश के अंदर मुसलमानों के साथ भेदभाव

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के खिलाफ अपना तीखा हमला बोलते हुए उन्हें सबसे बड़ा घुसपैटिया बताया और चेतावनी दी कि राज्य को निशाना बनाने वालों को नरक में जाना पड़ेगा। ममता ने आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों का एसआईआर बंगाल में अगले महीने होने वाले चुनावों को प्रभावित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।



बंगाल चुनावों से पहले अवैध अप्रवासन एक अहम मुद्दा बनकर उभरा है, और प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों का कहना है कि बड़े पैमाने पर घुसपैट ने राज्य की जनसंख्या संरचना को बदल दिया है। भाजपा ने ममता बनर्जी पर तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणियों से चुनाव हारने का उनका अत्यधिक भय झलकता है। भाजपा नेता शिशिर बाजोरिया ने कहा जो कोई भी देश के प्रधानमंत्री को घुसपैटिया कहता है, उसे संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। लगातार चौथी बार सत्ता में आने की उम्मीद कर रही तेजतर्रार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घुसपैट के मुद्दे को एसआईआर प्रक्रिया से जोड़ने की कोशिश की, जो चुनावों से पहले एक बड़ा विवाद का मुद्दा बन गई है।

अब असम में भाजपा को लगा बड़ा झटका

» मंत्री नंदिता गरलोसा कांग्रेस में शामिल, हाफलोंग से लड़ेंगी चुनाव

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

गुवाहाटी। असम विधानसभा चुनाव 2026 के मतदान से ठीक पहले राज्य की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। हिमंत विश्व शर्मा सरकार में खेल और युवा कल्याण मंत्री नंदिता गरलोसा ने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। गरलोसा ने यह कदम आसन्न असम विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा से टिकट नहीं मिलने के बाद उठाया। कांग्रेस द्वारा जारी बयान के मुताबिक गरलोसा आसन्न असम विधानसभा चुनाव में दिमा हसाओ जिले के हाफलोंग जिले से पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस ने पहले इस सीट से अपने राज्य इकाई के महासचिव निर्मल लंगथासा को मैदान में उतारा था।

लेकिन उन्होंने 'व्यापक जनहित' में



गरलोसा को पार्टी का टिकट देने पर सहमति जताई है। पार्टी ने एक बयान में कहा, हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि नंदिता गरलोसा कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। वह पिछले पांच वर्षों से दीमा हसाओ की आवाज रही हैं और उन्होंने हमेशा अपने विश्वासों तथा सिद्धांतों के लिए दृढ़ता से खड़ी रही हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य की खेल और युवा कल्याण मंत्री को भाजपा में इसकी कीमत चुकानी पड़ी

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप

कांग्रेस ने भाजपा और मुख्यमंत्री पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि हिमंत विश्व शर्मा की सरकार केवल आदिवासियों की जमीनें बड़ी कंपनियों को बेचने में रुचि रखती है। पार्टी के अनुसार, जो नेता आदिवासियों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं, उन्हें भाजपा दरकिनार कर रही है। नंदिता गरलोसा के दल बदलने से दीमा हसाओ जिले में चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं, जिसे हाफलोंग सीट पर अब मुकाबला बेहद कड़ा होने की उम्मीद है।

क्योंकि हिमंत विश्व शर्मा को केवल आदिवासियों की जमीनें बड़ी कंपनियों को बेचने में दिलचस्पी है। गरलोसा निवर्तमान विधानसभा में हाफलोंग का प्रतिनिधित्व करती हैं। भाजपा ने इस बार इस सीट से रुपाली लांगथासा को अपना उम्मीदवार बनाया है। असम कांग्रेस की मीडिया टीम ने हाफलोंग में गरलोसा के पार्टी में शामिल होने की एक तस्वीर साझा की। तस्वीर में राज्य के खेल और युवा कल्याण मंत्री गरलोसा कांग्रेस नेता निर्मल लंगथासा और अन्य लोगों के साथ नजर आ रही हैं।

एलाएसजी को सहयोग देगा केईआई

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। केईआई ने इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 19 जो 28 मार्च से शुरू हो रहा है के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ प्रिंसिपल पार्टनर के रूप में एक रणनीतिक साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य पूरे भारत में व्यवसायिक उपस्थिति को और मजबूत करना है। आईपीएल देश के प्रमुख क्रिकेट स्टेडियमों में आयोजित होगा, जो ब्रांड विजिबिलिटी और एंगेजमेंट के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगा।

केईआई जमीनी स्तर पर क्रिकेट को बढ़ावा देने और वंचित वर्ग के युवा खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल भी कर रहा है, जो अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों को प्रेरित करने की उसकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस पहल को प्रतिष्ठित क्रिकेटर्स जैसे ऋषभ पंत, मयंक यादव, अर्जुन तेंदुलकर अन्य खिलाड़ी सहित एलाएसजी टीम के अन्य प्रमुख खिलाड़ियों की गरिमामयी उपस्थिति में प्रस्तुत किया जा रहा है।

आईपीएल 2026 : मुंबई की नजर छटे खिताब पर

» रोहित-रिकेल्टन दिलाएंगे आतिथी शुरुआत, मुंबई के ऑलराउंडर्स हैं खतरनाक

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। आईपीएल के 19वें सीजन में पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस एक बार फिर खिताब की मजबूत दावेदार के रूप में उतरने जा रही है। टीम कागज पर बेहद संतुलित नजर आ रही है, जहां बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक हर विभाग में गहराई दिखाई देती है। तो क्या हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस छठी बार ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी। मुंबई की बल्लेबाजी इस सीजन उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर सकती है।

रोहित शर्मा के अनुभव के साथ रेयान रिकेल्टन और क्विंटन डिकॉक जैसे

आक्रामक बल्लेबाज मौजूद हैं, जिनमें से कोई भी पारी की शुरुआत करते हुए नजर आ सकता है। मुंबई की सबसे बड़ी खासियत उसका मजबूत ऑलराउंड डिपार्टमेंट भी है। कप्तान हार्दिक पांड्या के अलावा विल जैक्स, शार्दूल ठाकुर और कॉर्बिन बॉश जैसे खिलाड़ी टीम को जबर्दस्त संतुलन देते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह टीम की अगुवाई करते नजर

आएंगे, जिनका साथ ट्रेट बोल्ट और दीपक चाहर जैसे अनुभवी गेंदबाज देंगे। स्पिन विभाग में भी मिचेल सैंटनर और अल्लाह गजनफर टीम को विविधता प्रदान करते हैं, जबकि मयंक मार्कंडेय भी अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। अगर टीम के प्रमुख खिलाड़ी अपनी लय बरकरार रखते हैं और कप्तान हार्दिक पांड्या सही रणनीति अपनाते हैं, तो मुंबई इंडियंस के पास आईपीएल 2026 में छठी बार खिताब जीतने का सुनहरा मौका होगा।



मजबूत बल्लेबाजी के दम पर उतरेगी दिल्ली

नई दिल्ली। दिल्ली कैपिटल्स एक बार फिर अपने पहले खिताब की तलाश में मैदान पर उतरने जा रही है। अक्षर पटेल की कप्तानी में टीम इस बार संतुलित बल्लेबाजी लाइनअप के साथ नजर आ रही है, लेकिन तेज गेंदबाजी आक्रमण की कप्तानी उनके लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। क्या इस बार दिल्ली का लंबा इंतजार खत्म हो पाएगा या नहीं। केएल राहुल पिछले सीजन शानदार लय में नजर आए थे और इस बार भी उनसे टीम को बड़ी उम्मीदें होंगी। उनके अलावा ट्रिस्टन स्टब्स ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से काफी प्रभावित किया था, जबकि अभिषेक पोरेल ने भी लगातार अच्छे प्रदर्शन करके अपनी उपयोगिता साबित की थी। टॉप ऑर्डर में टीम के पास अच्छे विकल्प मौजूद हैं। इनके अलावा प्रवीण शॉ के रूप में दिल्ली के पास दो आक्रामक सलामी बल्लेबाज हैं, जो टीम को तेज शुरुआत दिला सकते हैं। वहीं, नीतीश राणा का अनुभव मिडिल ऑर्डर को मजबूत देता है। इसके अलावा डेविड मिलर को टीम में शामिल करने से बल्लेबाजी और भी संतुलित नजर आती है, जो मुश्किल परिस्थितियों में पारी को संभालने के साथ-साथ तेजी से रन भी बना सकते हैं।

लोकसभा में जोरदार हंगामा बना पक्ष-विपक्ष में वार-पलटवार

» कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक पर कांग्रेस का घोर विरोध, बैकफुट पर सरकार

» सरकार ने विचार-विमर्श के लिए जेपीसी को भेजा

» 4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। लोकसभा में आज भी जोरदार हंगामा बना रहा। संसद में पेश कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक पर सरकार और विपक्ष के बीच घारे मतभेद दिखे, जिसके बाद सरकार ने इसे व्यापक विचार-विमर्श हेतु जेपीसी को भेजने का निर्णय लिया। कांग्रेस ने प्रमुख नीतिगत मामलों को अधीनस्थ कानूनों पर छोड़ने का विरोध किया है, जबकि सरकार का लक्ष्य व्यवसायों के लिए मुकदमेबाजी का जोखिम कम करना है।

कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजने का प्रस्ताव रखा। सदन ने इस पर सहमति जताते हुए विधेयक को जेपीसी को भेज दिया। विधायक द्वारा विधेयक पेश किए जाने पर उठाई गई आपत्तियों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष ने जेपीसी द्वारा समीक्षा की मांग नहीं की थी। उन्होंने आगे कहा कि विधेयक को समिति को भेजने



कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने उठाए सवाल

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 को पेश किए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कंपनियों का वर्गीकरण, सूट, अनुपालन आवश्यकताओं का निर्धारण, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की सीमा, लेखापरीक्षा दायित्व और दंड ढांचे जैसे प्रमुख नीतिगत मामलों को पर्याप्त विधायी मार्गदर्शन के बिना बार-बार निर्धारित प्रावधानों के उपयोग के माध्यम से अधीनस्थ कानूनों पर छोड़ दिया गया है। विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसी महीने की शुरुआत में मंजूरी दी है। इस विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसी महीने की शुरुआत में मंजूरी दे दी है और यह कंपनी विधि समिति (2022) की सिफारिशों के साथ-साथ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से प्राप्त सुझावों पर आधारित है। इसमें दो प्रमुख कानूनों - कंपनी अधिनियम, 2013 और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 - में संशोधन का प्रस्ताव है, जो मिलकर पूरे भारत में कॉर्पोरेट संस्थाओं और एलएलपी को नियंत्रित करते हैं। मूल रूप से, इस विधेयक का उद्देश्य अनुपालन के बोझ को कम करना, छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और समय के साथ उभरे नियामकीय अंतरालों को दूर करना है।



का निर्णय सरकार का था ताकि इस कानून पर व्यापक चर्चा हो सके। प्रमुख अपेक्षित प्रावधानों में से एक है छोटे कॉर्पोरेट अपराधों को और अधिक अपराध की श्रेणी से बाहर करना, जो प्रक्रियात्मक चूक के लिए

आपराधिक दंडों को मौद्रिक जुर्माने से बदलने के सरकार के पूर्व दृष्टिकोण को जारी रखता है। इसका उद्देश्य मुकदमेबाजी के जोखिम को कम करना और व्यवसायों के लिए परिचालन तनाव को कम करना है।

उन्नाव के जिला पंचायती राज विभाग में बड़ा खेल!

» एक ही फर्म को 1.90 करोड़ का भुगतान

» छह ब्लॉकों में एक ही फर्म का दबदबा भुगतान पर उठे सवाल

» 4पीएम न्यूज नेटवर्क

उन्नाव। उन्नाव जिला पंचायती राज विभाग में अनियमितताओं का बड़ा मामला सामने आया है जहां एक ही फर्म को करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपये की सामग्री आपूर्ति के नाम पर भुगतान किए जाने से घोटाले की आशंका गहरा गई है। मामला सामने आते ही विभागीय कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

जानकारी के मुताबिक नवाबगंज, बिछिया, पुरवा, सुमेरपुर, हसनगंज और सिकंदपुर कर्ण जैसे कई ब्लॉकों में जय बुद्धवा बाबा इंटरप्राइजेज नाम की एक ही फर्म को करोड़ों रुपये का भुगतान किया गया। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी राशि का कार्य एक ही फर्म को देने के पीछे क्या प्रक्रिया अपनाई गई इसका स्पष्ट जवाब अब तक सामने नहीं आया है।

पारदर्शिता पर सवाल, कार्रवाई की मांग तेज

इस पूरे मामले ने जिला पंचायती राज विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़ा प्रश्नचिह्न लगा दिया है। आमतौर पर सरकारी कार्यों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के तहत कई फर्मों को मौका दिया जाता है, लेकिन यहां एक ही फर्म को लगातार प्राथमिकता मिलना संदेह को और मजबूत करता है। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच में क्या सच सामने आता है और क्या वाकई यह मामला करोड़ों के घोटाले में बदलता है या नहीं।

असोहा ब्लॉक की फर्म को मिली विशेष तवज्जो, बढ़ी संदेह की सुई

सूत्रों के अनुसार संबंधित फर्म असोहा ब्लॉक में रजिस्टर्ड है लेकिन इसके बावजूद उसे जिले के कई अन्य ब्लॉकों में भी लगातार काम और भुगतान दिया गया। इससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या टेंडर प्रक्रिया का पालन किया गया या फिर नियमों को दरकिनारा कर एक ही फर्म को लाभ पहुंचाया गया। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा जोरों पर है कि विभागीय अधिकारियों और फर्म के बीच सांतगांध के चलते यह पूरा खेल रचा गया। यदि यह आरोप सही साबित होते हैं तो यह मामला बड़े वित्तीय घोटाले में तब्दील हो सकता है।

शासन ने दिए जांच के आदेश, विभाग में मचा हड़कंप

मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन स्तर से जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जांच टीम अब यह पता लगाएगी कि आखिर किन परिस्थितियों में एक ही फर्म को इतने बड़े स्तर पर भुगतान किया गया और क्या इसमें वित्तीय नियमों का उल्लंघन हुआ है। जांच के आदेश मिलते ही विभाग में हड़कंप मच गया है। संबंधित अधिकारी अब अपनी-अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश में जुटे हैं जबकि दस्तावेजों की जांच शुरू हो चुकी है।

अमेरिका में एयरपोर्ट पर हुए हादसे में 2 पायलटों की मौत

» 4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित ला गार्डिया एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा हो गया, जहां रनवे पर एयर कनाडा एक्सप्रेस का विमान ट्रक से टकराया। इस हादसे में विमान में सवार 100 से अधिक यात्रियों के घायल होने की भी खबर है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस विमान हादसे में पायलट और सह-पायलट की मौत हो गई।

घटना की शुरुआती जांच में सामने टकरा से कुछ पल पहले ही पायलट और वाहन चालक दोनों को रुकने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद हादसा नहीं टल सका। फ्लाइट-ट्रैकिंग वेबसाइट ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि हवाई अड्डे पर लोगों को निकालने के लिए राहत बचाव का कार्य



जारी है। घटना के तुरंत बाद अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने सुरक्षा कारणों से हवाई अड्डे पर सभी उड़ानों के लिए ग्राउंड स्टॉप जारी कर दिया है। यानी सभी उड़ानों पर रोक लगा दी गई है।

दिल्ली के बजट सत्र का आगाज

» विधायकों के निलंबन पर आप का बहिष्कार

» 4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। रेखा सरकार दूसरी बार बजट पेश करने जा रही है। बजट सत्र की शुरुआत खीर सेरेमनी के साथ की गई। दिल्ली बजट सेशन 2026 से पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों परवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, कपिल मिश्रा और अन्य लोगों के साथ खीर सेरेमनी की, जहां स्कूली छात्राओं को खीर खिलाई गई।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, बजट 2026-27 यह हमारी सरकार का दूसरा बजट है। यह दिल्ली के विकास की गति बढ़ाने वाला बजट है। यह दिल्ली के लोगों के जीवनस्तर को ऊपर उठाने वाला बजट है। यह दिल्ली के विकास को अधिक



गति देगा विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने अपने काम से देश और दुनियाभर में भारत का मान बढ़ाया है, उन्होंने आशीष सूद की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन प्रस्ताव के लिए सदस्यों की सहमति मांगी, जिसका ध्वनिमत से सभी सदस्यों ने समर्थन किया। वहीं, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन सदन से बायकांट किया है, विपक्ष के चार विधायकों को पिछले शीतकालीन सत्र से निष्कासन बरकरार रखने पर आम आदमी पार्टी के

विपक्ष की आवाज दबाने के अलावा कोई काम नहीं : आतिशी

वहीं, बजट सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर आम आदमी का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता और आप विधायक आतिशी ने कहा, विधानसभा के सत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका होती है। विपक्ष की भूमिका होती है सरकार को जनहित के मुद्दों के बारे में बताना लेकिन माजपा ने पिछले 1 साल में विपक्ष की आवाज दबाने के अलावा कोई काम नहीं किया। यह कैसा लोकतंत्र है। वे विधानसभा का सत्र क्यों बुला रहे हैं, जब विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता है।



सभी विधायकों ने विरोध किया है। सदन में अनुपस्थित हैं। पिछले विधानसभा सत्र में भी पहले दिन के बाद विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी सदन से गायब रही थी।

यूपीए कानून के दुरुपयोग के बढ़ते मामलों पर भड़के न्यायाधीश भुइयां

» सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पृथ्वी-एसे बनेगा विकसित भारत

» 4पीएम न्यूज नेटवर्क

बेंगलुरु। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उज्जल भुइयां ने विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो इसके लिए समाज और शासन व्यवस्था में व्यापक सुधार आवश्यक हैं। खासतौर पर विचारों की स्वतंत्रता, असहमति का सम्मान और सामाजिक समानता इस दिशा में मूल आधार बनने चाहिए।

हम आपको बता दें कि बेंगलुरु में आयोजित उच्चतम न्यायालय बार



एसोसिएशन के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए न्यायाधीश भुइयां ने स्पष्ट कहा कि किसी भी विकसित राष्ट्र, का निर्माण केवल आर्थिक प्रगति से नहीं होता, बल्कि सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती से होता है। उन्होंने कहा कि बहस और असहमति

लंबे समय तक किसी व्यक्ति को जेल में रखना न्याय के मूल सिद्धांत के विपरीत

न्यायाधीश भुइयां ने यह भी कहा कि बिना आरोप पत्र दखिल किए लंबे समय तक किसी व्यक्ति को जेल में रखना न्याय के मूल सिद्धांत के विपरीत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद का सिद्धांत कमजोर पड़ता जा रहा है, जिससे न्याय व्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इससे अदालतों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ती है और न्याय मिलने में देरी होती है।

संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए

विकसित भारत की अवधारणा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश में संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए और आर्थिक असमानता समाप्त होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी निर्धारित किया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायपालिका को अपनी स्वतंत्र भूमिका बनाए रखनी चाहिए। वह न तो स्थायी आलोचक बन सकती है और न ही किसी सरकारी अभियान की समर्थक।

को अपराध की श्रेणी में डालना एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।

समाज में विभिन्न विचारों को सम्मान मिलना चाहिए और आलोचना को सहन करने की क्षमता विकसित करनी होगी। उन्होंने गैर कानूनी गतिविधियां निवारण कानून यानि

यूपीए के तहत हो रही गिरफ्तारियों पर भी चिंता व्यक्त की। आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2023 के बीच हजारों लोगों को इस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया, लेकिन दोष सिद्ध होने की दर लगभग पांच प्रतिशत ही रही। उन्होंने

कहा कि इसका अर्थ यह है कि अधिकांश मामलों में या तो पर्याप्त साक्ष्य नहीं था या फिर गिरफ्तारी जल्दबाजी में की गई। उन्होंने कहा कि यदि 95 प्रतिशत मामलों में आरोपी बरी हो रहे हैं, तो यह कानून के अधिक उपयोग या दुरुपयोग की ओर संकेत करता है।